

E Content - History - B.A. Hons. III<sup>rd</sup> year  
 Paper - VI - Indian National Movement

Prof. Paswan Choudhury  
 Chief Coordinator History,  
 Nalanda Open University.

Ques. - what was the Role of Moderates  
 in the Indian National Movement  
 (1885 - 1905)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी  
 विचारों की भूमिका (1885 - 1905) क्या थी।

Ans. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास  
 कांग्रेस का ही इतिहास है। कांग्रेस के नेतृत्व  
 में ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप  
 हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को विदेशी शासन  
 से मुक्त करना था। कांग्रेस ने 1885 ई. से 1947 ई.  
 तक ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लगातार आंदोलन  
 किया और उसी के फलस्वरूप ही भारत को स्व-  
 र्रता मिली। 1885 ई. अर्थात् कांग्रेस के स्था-  
 पना - वर्ष 1947 ई. तक के भारतीय राष्ट्रीय  
 आंदोलन के इतिहास को अध्ययन की सुविधा  
 के लिए तीन चरणों में बांटा जा सकता है -

- 1) प्रथम चरण : उदारवादी युग (1885-1905)
- 2) द्वितीय चरण : उग्रवादी युग (1905-19)
- 3) तृतीय चरण : गांधी - युग (1919-47)



भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण : उदारवादी युग (1885-1905)

कांग्रेस के प्राथमिक उद्देश्य - प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना नहीं था। यह भारत के शिक्षित तथा मजि-  
 मात वर्ग के लोगों की एक संस्था थी। यह सही माने में भारत की प्रतिनिधि सभा नहीं थी। इसके सदस्य नरम राष्ट्रीयता के पौषक थे और विनम्र शब्दों में सरकारी कार्यों की आलोचना कर उनमें सुधार के सुझाव देते थे। स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद तक कांग्रेस के अधिवेशन भारत के किसी प्रमुख शहर में होते थे, जहाँ सरकारी नीति की आलोचना कर सुधार के प्रस्ताव पास होते थे। ये प्रस्ताव बड़े विनम्र शब्दों में होते थे और सरकार के प्रति किसी प्रकार के विद्रोह का ज्ञापन नहीं रखते थे। चूंकि, सरकार से कांग्रेस का कोई विरोध नहीं था, इसलिए भारतीयता और अंग्रेजों की भी इसके कार्यों में भाग लेते थे। लॉर्ड डफ्रिन तथा मद्रास के गवर्नर ने क्रमशः कांग्रेस के वृद्धि और तीव्र अधिवेशन के अवसर पर भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सरकारी भवन में प्रीतिभोज दिया था।

उदारवादिता का प्रभाव - प्रारंभ में कांग्रेस प्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समूह उस-  
 की बागडोर नरम राष्ट्रवादिता के हाथ में थी। नरम राष्ट्रवादिता की अंगरेजी की न्यायप्रियता में बृद्धि आरम्भ थी। उनका प्रमुख दृष्टिकोण था अंगरे-  
 जीय शासन का प्रजातंत्रिकरण तथा विद्यालयों में



में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि। वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राज भक्ति दिखाते थे और राजनीतिक जागरण के लिए अपने को अंगरेजों का कृतज्ञ मानते थे। काँग्रेस के बारहवें अधिवेशन में मुहम्मद रहीमतुल्ला ने कहा था, "अंगरेजों से अधिक से अधिक इसानदार और शक्ति संपन्न जाति सुन्ने के नीचे और कोई नहीं है। चूंकि उदारवाद नेताओं का अंगरेजों की व्यापक प्रियता से अटूट विश्वास था, इसलिए वे वैधानिक आंदोलन द्वारा ही अपनी मांगों की पूर्ति करने का प्रयास करते थे। वे प्रायः शासक पक्ष, सम्राज्यपक्ष तथा प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी व्यापक मांगों को मानने का आग्रह करते थे। उदारवादी युग में काँग्रेस द्वारा कई राजनीतिक मांगें पेश की गई थीं -

- (i) धारा - समा का विस्तार और उसके सदस्यत्व को द्वारा निर्वाचित हो
  - (ii) केंद्रीय तथा प्रांतीय धारा - समाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि लाई जाऊ
  - (iii) व्यापक व्यवस्था में पूरी का प्रयोग हो
  - (iv) परिषद में तथा उच्च नौकरियों में भारतीयों को स्थान मिले तथा भारतीयों की उच्च सैनिक शिक्षा दी जाय।
- (v) शरत कावृण में संशोधन लाया जाऊ।
- (vi) 1905 ई० में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त शासन की मांग की। 1906 ई० में इसी मांग को दादाभाई नौरोजी ने पुनरावृत्त किया।
- काँग्रेस ने सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में आवेक शक सुधार लाने के लिए कुछ मांगें रखी थीं -



Page 4

- (i) भूमि कर में कमी की जाए।
- (ii) सिन्धुई की उचित व्यवस्था हो
- (iii) भारतीय उद्योग - व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाए।
- (iv) भारत से बाहर भेजे जाने वाले अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- (v) शासन के व्यय में कमी की जाए
- (vi) नमक - कर को समाप्त किया जाए

सरकार की नीति में परिवर्तन और उसके परिणाम - आरंभ में ~~काँग्रेस~~ काँग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश कूटनीति को महान विरोध सामना पाना था। परंतु, सरकार और काँग्रेस के बीच यह मध्य संबंध अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। घुम के उद्देश्य सच्चे और प्रशासनीय थे। शुभ काँग्रेस द्वारा भारतीयों की सेवा करना चाहता था। परंतु, शीघ्र ही सरकार इस संगठन से सशर्तित हो गई और उसे इसमें बृहत्तर विश्वास देने लगा। सरकार ने काँग्रेस को प्रोत्साहन देना छोड़ दिया। 1888 ई. में सरकार की काँग्रेस - संबंधी नीति में परिवर्तन हुआ। लॉर्ड डफ्रिन ने एक मंत्र के अवसर पर कहा, "अब काँग्रेस का मुकाबला राष्ट्रप्रेम की ओर हो गया है और यह संस्था शिक्षित भारतीयों के नाममात्र का प्रतिनिधित्व करती है।" 1990 ई. में सरकार ने एक विज्ञापित निकाली जिसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को काँग्रेस के अधिपति शासन में शामिल होने की मनाही की गई। मुसलमानों को भी काँग्रेस के कार्यों से अलग रखने की चेष्टा होने लगी। इस प्रकार, सरकार एवं काँग्रेस के आपसी संबंधों में कटुता बढ़ने लगी।

सरकार के इस बदलते दुरु रुख के बावजूद काँग्रेस अपने शस्त्र पर चलाती रही। निःसंदेह काँग्रेस की



कार्य नीति में कुछ परिवर्तन आया। कांग्रेस के नेताओं ने वाचसराय के विचारों का संतुलन करना शुरू किया। धीरे-धीरे कांग्रेस की ओर से देश के विभिन्न भागों में सभाओं की जाने लगी और राष्ट्रीय भावों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव होने लगे। किंतु, अब भी कांग्रेसी नेताओं का अंगरेजों में विश्वास था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने पूना कांग्रेस में भाषण देते हुए भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बताया। इंग्लैंड में भी कांग्रेस के कार्यों का प्रचार होने लगा, जिसमें कुछ अंगरेजों ने भी दिलचस्पी दिखाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चार्ल्स क्रैडला और सर विलियम वेडबर्न के नाम इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं; जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1890 ई. में इंडियन पार्लियामेंटरी कमिटी की स्थापना हुई। इस कमिटी ने 1890 ई. में 'इंडिया' नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की, जो 1892 ई. में मासिक और 1896 में साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 1892 ई. में इंडियन कांसिल बिल (Indian Councils Act, 1892) पास हुआ, जिससे भारतीय विधानसभों के कुछ सुधार हुए, पर सुधार - अधिनियम कांग्रेस के प्रयत्नों का ही प्रतिफल था। परन्तु, कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। यही नहीं, भारतीयों को जो वर्ग-बहुत राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, उनपर भी कुठराव्याप्त करना अपर्याप्त माना गया। 1899 ई. में कलकत्ता कांग्रेस के भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1905 ई.



में प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। वाल  
गंगाधर तिलक को तथा अनेक समाचारपत्रों  
के सम्पादकों को कैद कर लिया गया। इससे  
उदारवादिनों में अल्पदिक असंतोष हुआ। सरकारी  
भी कांग्रेस के प्रस्तावों को लुकारती रही, अतः कांग्रेस  
के कुछ सदस्यों को विश्वास ही गया कि केवल  
प्रस्ताव पारित करने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं  
होगी, इसके लिए कुछ अधिक ठोस कदम उठाने  
होंगे।

तिलक का पदापण - उदारवादिनों के समर्थ ही  
भाषीय राजनीतिक शीर्षक पर वालगंगाधर तिलक  
का पदापण हुआ। उनका कहना था कि कांग्रेस की  
नरमी और राजसक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने में  
बाधाक है। केवल प्रस्ताव पास करने तथा अंगरेजों  
के सामने हाथ पसारने से राजनीतिक अधिकार  
प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए आन्दोलन करना  
हीगा। वालगंगाधर तिलक का प्रथम हुआ था।  
तिलक बहुत बड़े विद्वान और सफल पत्रकार थे।  
संस्कृत, मराठी और अँगरेजी भाषा में वे पारंग-  
गत थे। उनका विश्वास था कि जो अपने पैरों पर  
नहीं खड़ा होता उसकी सहायता ईश्वर ही नहीं  
करते। वे महान देशभक्त थे और उनका दृढ़ विश्वास  
विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के अंत के बिना देश  
का कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने गणपति स्वामी  
राष्ट्र और शिवजी मन्तार का आशीर्वाद कर लेना  
की धार्मिक भावना को प्रगाथा तथा उनसे राष्ट्र  
के प्रति भक्ति पैदा की। उन्होंने विचारियों के लिए  
अनुशासन तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर अधिक  
और दिया, ताकि युवकों में साहस का विकास  
हो और वे निष्पक्ष लोकप्रिय आंदोलन में भाग  
ले सकें। महाराष्ट्र के युवकों ने भी तथा स्वदेश-  
प्रेम उत्पन्न करने में तिलक बहुत - कुछ सफल हुए  
इसमें उन्हें महाराष्ट्र के आर्थिक संकट से ही  
सहायता मिली। उस समय महाराष्ट्र अकाल  
और प्लेग का शिकार था। इससे ब्रिटिश शासन



कौं विरुद्ध लौगीं में व्यौर असंतोष फैल रहा था।  
 तिलक - जिन्हे अंगरेज भारतीय अशांति का  
 जनक कहकर पुकारते थे - राजद्रोह में गिरफ्तार  
 कर लिये गए और उन्हें अठारह माह के कारा-  
 वास का सजा दी गई। किंतु कुछ कारणों से  
 सजा छूट महीनों की कर दी गई। सरकार की  
 इस दमनकारी नीति का विपरीत फल हुआ।  
 तिलक की गिरफ्तारी से भारतवासी सुबुद्ध  
 हो उठे और देश में व्यौर असंतोष फैल गया।  
 गिरसंदेह, कुछ समय के लिए राष्ट्रीय प्रजाति  
 रुक गई थी और भारत के राजनीतिक जागृता  
 में शांति कायम हो गई थी, किंतु यह शांति  
 आगेवाले संस्कारों का धोका थी, जो 1905  
 ई० से पूर्व पड़ी।

1905 ई० तक काँग्रेस पूर्णतः उदारवादिनों तथा  
 नरसत्त्वों के प्रभाव में थी, जो अंगरेजों की  
 साम्राज्यशासन तथा सत्कार से विश्वास करते थे। वे प्रायः  
 नापत्रों तथा प्रातःनिधि - मंडलों के माध्यम से सरकार  
 से अपनी मांगों को मानने का अनुरोध करते थे।  
 शांति से किसी सहत्वपूर्ण या सुलभ परिणतन  
 के सम्बन्ध नहीं थे, अपितु परिषदों, सरकारी  
 सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और रक्षा सेनाओं  
 के क्रमिक सुधार की मांग करते रहे। दादाभाई  
 नौरोजी, सुबुद्ध बनर्जी, रु. ओ० धूम, गोपाल -  
 कृष्ण गोखले, सर चिरीपट्टाई मेहता और महदेव  
 गोविंद वण्डे प्रमुख उदारवादी नेता थे। सुसुखविश्व-  
 लाल सिंह के शब्दों में, "आरंभ से काँग्रेस द्वारा राजस-  
 क्त की प्रतिज्ञा, नरस नीति, आरंभ की नहीं करन सिद्ध।  
 वृत्ति की नीति अपनाते पर भी, उन्होंने यह सम्य राष्ट्रीय  
 जागरण, राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों को रुक सूत्र  
 में जाँचने और उनसे सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता  
 की भावना के निर्माण में बहुत अधिक सहयोग दिया।



उदार राष्ट्रियता का मूलधारण - 1885 ई. के 1905 ई. तक काँग्रेस उदारवादिता का गढ़ बनी रही। शासन में उदार राष्ट्रवादिता के जो कार्य किए उनमें कई दृष्टियाँ थी -

क) ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निर्यात व्यापार - उदारवादी नेता यह समझते नहीं सके कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक आधार क्या है अथवा उसकी क्या प्रवृत्ति है। शासन और शासित के स्वाभाव परस्पर - विरोधी होते हैं। उदारवादी नेताओं का यह अनुमान गलत था कि अंगरेजों और भारतीयों के हित परस्पर - विरोधी न होकर एक - दूसरे के साथ जुड़े हैं। उदारवादी अंगरेजों की व्यापारप्रियता के प्रति आवश्यकता से अधिक आशङ्कित थे। एक आधुनिक लेखक का यह कहना है कि उदारवादिता की असफलता का यह कारण था कि उन्हें अंगरेजों की अपराधीता पर विश्वास था और वे समझते थे कि पूँजीपतियों के उत्पादन की प्रक्रिया ही सबसे अच्छी है। वे भूल गए कि ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण और राजनीतिक पराधीनता है। जब उनकी हानि लोगों की अस्वीकार कर दी गई तो उनका मोह - संग हुआ।

(ख) राष्ट्रीय तत्वों का अभाव - काँग्रेस की स्थापना का आधार शिक्षित भारतीयों का सहयोग था। जनसाधारण के बीच उनकी पैठ नहीं थी। लाला लजपत राय ने लिखा है, "पत्रार्थ में काँग्रेस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वों की कमी थी। यह आंदोलन न तो जनता द्वारा संयोजित था और न उसके द्वारा अनुप्राणित ही। उदारवादिता की सफलताएँ - उदारवादिता के कार्यक्रमों में दृष्टियाँ थीं और उन्हें अपने उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं मिली। इस कारण लोगों



उन्के महत्व को बतार अंदाज कर देते थे।  
 उन्होंने सुलभ और सरकारी सरकार का सामना  
 नहीं किया, क्योंकि वे तब तक ही पहुँचि स्थिति  
 में विवश थे। यदि वे उग्र नीति अपनाते तो आरंभ  
 में ही सरकार कठोरता से उन्हें दबा देती। ऐसी परिस्थिति  
 में उन्होंने जो सेवा भारत के लिए की वह भी न हो पाती।  
 वे भारतीय राष्ट्रियता के अग्रदूत थे, इसे अस्वीकार  
 नहीं किया जा सकता। वस्तुतः, कांग्रेस के उदारवादी  
 नेताओं के अग्रदूत थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा  
 सकता। वस्तुतः, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रयास  
 से ही भारत में राष्ट्रियता की जड़ बँधी थी। उन्हें  
 के प्रयास से औपनिवेशिक स्वशासन तथा प्रशास-  
 निक अ्यार की माँगों की जाने लगी थी। भारतीयों को  
 राजनीतिक प्रशिक्षण दिवाने की शिक्षा में उनका योगदान  
 प्रशंसनीय था।

उदारवादिओं के प्रयास से ही 1892 ई. का भार-  
 तीय परिषद अधिनियम पारित हो सका था।  
 भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के विकास में यह  
 एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था।

उदारवादिओं के राजनीति पर प्रभाव से रोक  
 लाना अवश्य हुआ। राष्ट्रवादिओं के हृदय में आत्म-  
 विश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना जागृत  
 हुई। वे धीरे-धीरे समझने लगे कि ब्रिटिश शासन  
 उनका कल्याण करना नहीं चाहती है।

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम की नींव इन्हीं बीस  
 वर्षों में उदारवादिओं के प्रस प्रयास से डाली गई।  
 उदारवादी नेताओं ने ही हमें इस योग्य बनाया कि  
 हम स्वतंत्रता की माँग सरकार के समक्ष रख  
 सकें। डॉ. पट्टाभि सतीरमैया ने उदारवादिओं के कार्यों  
 की प्रशंसा में यह विचार व्यक्त किया है, "प्राथमिक  
 राष्ट्रवादिओं ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की श्मार्त



की भीव आती। उनके प्रयत्नों से ही इस  
 जीव पर एक - एक संश्लेष करके इलाहाबाद आती  
 गयी गई। पहले उपनिवेशों के द्वारा का स्व-  
 शासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होना और  
 इसके ऊपर स्वराज्य और सबसे ऊपर पूर्ण  
 स्वाधीनता की संश्लेषें बन सकी हैं।"

